मौलिक कर्तव्यों को लागू करना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था, शासन और आईआर) से संबंधित है।

द हिन्दू

05 अप्रैल, 2022

नागरिकों पर कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं

अटॉर्नी-जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए विशिष्ट कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वेणुगोपाल ने एक संवैधानिक कार्यालय के रूप में अपनी क्षमता में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के कानून बनाने के लिए संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकता है।

वकील की याचिका

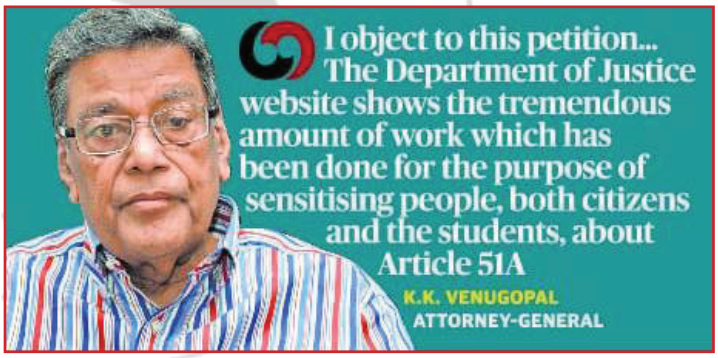

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अदालत ने देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को व्यापक, अच्छी तरह से लागू करने में बहुत सावधानी बरती है। (परिभाषित कानून)

श्री वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता के शोध की कमी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर उन्होंने देखने की परवाह की होती, तो कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट ने उन्हें जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए 'जबरदस्त काम' का विस्तृत विवरण दिखाया होता। (मौलिक कर्तव्य)

श्री दत्त ने यह जानना चाहा था कि न्यायमूर्ति जे.एस. "मौलिक कर्तव्यों के संचालन" पर वर्मा समिति की रिपोर्ट, समिति का काम संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा था। रिपोर्ट में सरकार से लोगों को उनके कर्तव्यों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील बनाने और सामान्य जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया गया था।

इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था।

"मैं इस याचिका का विरोध करता हूँ... न्याय विभाग की वेबसाइट अनुच्छेद 51ए के बारे में लोगों, नागरिकों और छात्रों दोनों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किए गए जबरदस्त काम को दिखाती है। कर्तव्य स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं... राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समय-समय पर इस पहलू को संबोधित किया है। एक साल का जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, "श्री वेणुगोपाल, जिन्हें अदालत की सहायता के लिए बुलाया गया था, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया।

सरकार हलफनामा दाखिल कर सकती है

हालाँकि, अदालत ने कहा कि सरकार एक हलफनामा दाखिल कर सकती है, जिसके आधार पर पीठ याचिका पर विचार कर सकती है।

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर-जनरल के कार्यालय के लिए उपस्थित वकील, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए सहमत हुए। अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में मामले को सूचीबद्ध किया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।
2. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा जोड़ा गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. 42nd Amendment Act of 1976 added 10 Fundamental Duties to the Indian Constitution.
2. Fundamental duties in the indian constitution were added by the recommendations of swaran singh committee in 1976.

Which of the above statements is /are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. आलोचनात्मक परीक्षण करें कि लोकतंत्र के लिए मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों है? (250 शब्द)

Q. Examine critically why fundamental duties are required for democracy? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।